भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 187
उत्तर देने की तारीखः 03.02.20202

नई शिक्षा नीति

†**187. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:**
श्री जुएल ओराम:
डॉ. शशि थरूर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने का विचार है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या प्रारूप नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो उक्त नीति के आरंभ होने का प्रत्याशित समय क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त नीति पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से क्या विचार और सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) प्रारूप दस्तावेज त्रिभाषा फार्मूले सहित प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(च) क्या यह सच है कि मई, 2019 में अपने गठन के बाद और उक्त नीति सहित सरकार द्वारा 100 दिनों की कार्ययोजना बनाई गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ङ): सरकार भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से, गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में लोगों की आवश्यकता की बदलती गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस उद्देश्य के लिए, गाँव से लेकर राज्य, आंचलिक स्तरों और राष्ट्रीय स्तर तक ऑनलाइन, विशेषज्ञ/विषयगत और जमीनी स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। प्रारंभ में, नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया

था, जिसने मई, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु कुछ इनपुट्स 2016 तैयार किए', दोनों दस्तावेजों को नीति निर्माण के लिए इनपुट माना जाता है। तदुपरांत, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने 31 मई 2019 को मंत्रालय को प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 (डीएनईपी 2019) प्रस्तुत की है। प्रारूप एनईपी 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf और https://innovate.mygov.in/list-nep/ पर विभिन्न हितधारकों से टिप्पणी और सुझाव प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया था। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को डीएनईपी 2019 पर उनके विचारों और टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखे गए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक और ओडिशा के माननीय सांसदों के साथ एक शिक्षा संवाद दिनांक 31.07.2019, 01.08.2019 और 02.08.2019 को लगातार तीन दिन तक आयोजित किया गया था। स्कूल शिक्षा के राज्य शिक्षा सचिवों और उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के राज्य सचिवों के साथ दो बैठकें क्रमशः 09.07.2019 और 08.08.2019 को आयोजित की गईं। विभिन्न हितधारकों से प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए| राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केब की एक विशेष बैठक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए दिनांक 21.09.2019 को आयोजित की गई थी| राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। प्रारूप एनईपी बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है और सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास और संवर्धन की अनुशंसा करता है। वर्तमान में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।

(च): यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों की कार्य योजना बनाई गई थी और अन्य विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि स्कूल शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और शैक्षणिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम (निष्ठा), वार्षिक पुनश्चर्या शिक्षण कार्यक्रम (अर्पित), नए केंद्रीय विद्यालयों का शुभारंभ, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम 2019, केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019, प्रतिष्ठित संस्थानों की घोषणा, प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव), के साथ नई शिक्षा नीति भी कार्यसूची में थी, जिसको अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।

****